

राज्य नागरिकों के चिन्तन के परिवर्तन की अपेक्षा करता है।
नागरिकों को कोई भी कार्य समाज के हित को ध्यान में रख
कर करना चाहिए। उन्हें यह अनुभव करना चाहिए कि वे समाज
के एक अंग हैं तथा उन्हें समाज के हित में मिल
कर कार्य करना चाहिए है। किसी व्यक्ति के कार्य से यदि
सम्पूर्ण समाज का अहित होता है, तो निश्चय ही समाज
का अंग होने के कारण उस व्यक्ति का भी अहित होगा।

- कार्य राज्य का उपलब्ध विवेक से रूपक है कि लोकहित
राजनीतिक सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा की आर्थिक सुरक्षा

- आर्थिक सुरक्षा - व्यक्ति की आर्थिक हित की सुरक्षा करना है।
कल्याणकारी राज्य का सर्वप्रथम उद्देश्य है। आर्थिक हित-सम
के अभाव में राजनीतिक हित साधना का कोई महत्व नहीं है।
इतिहास यह बताता है कि शासन का स्वल्प कोई भी रहा
राजनीतिक शक्ति उन लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है
जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं। अतः राजनीतिक
शक्ति को जन-साधारण में निहित करने के लिए यह अनिवार्य
है कि व्यक्तियों के एक-दूसरे के प्रति अधिक स्तर की प्रतिक्रिया
की व्यवस्था की जाए। लोक कल्याणकारी राज्य में किसी
व्यक्ति के लिए आर्थिक साधनों की अधिकता होने के
पूर्व सब व्यक्तियों के लिए उनकी अधिकता होने के
अनिवार्य है। यद्यपि आय की समता न तो सम्भव है
और ना ही वांछनीय है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति को
minimum economic standard उपलब्ध मिले।

- राजनीतिक सुरक्षा - लोककल्याणकारी राज्य का यह
उद्देश्य है कि वह व्यक्ति को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करे
जिससे व्यक्ति स्वयं राज्य के लोकहितकारी कार्य में सहयोग
दे सके और सामान्य हित में अपनी योग्यता को धीरे धीरे
के सहयोग से सके। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि व्यक्ति
को चाहिए कि अपना आचरण सामान्य हित सुरक्षा के अनु
सारे और अपने को उसके अधीन माने। यद्यपि तथापि उन्हें ह
वात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह उन सामान्य
इच्छा के निर्माण के विचार-आलोचना, प्रचार तथा
वैधानिक विरोध द्वारा अपना सहयोग दे सके। लोकहित
की साधना किसी-कालीन ही अथवा सामान्यकारी

जैसे अधिनायकवादी राज्य में भी हाँ लक्ष्मी है। (लेन एवं चीन जैसे साम्यवादी देशों में भी व्यापक लोकहित का साधन है भी रहा है, फिर भी लक्ष्य यह है कि आधिकारिक लक्ष्य को बेदी पर व्यापकता अपनी राजनैतिक लक्ष्य का बाधक करना पड़ा है। लोकहितकारी प्रजातंत्र लोकहितकारी साम्यवाद से उत्पन्न है क्योंकि साम्यवाद में व्यक्ति के केवल आर्थिक और सामाजिक हित का प्रधानता दी जाती है, जबकि प्रजातंत्र में राजनैतिक, कौटुंबिक आदि अन्य प्रकार के हितों का साधन भी उतनी ही महत्वपूर्ण समझी जाती है। प्रजातंत्रीय समाज तथा शासन सामान्य लोकनीति पर आधारित होता है। उसके द्वारा लोकहित पर आधारित कृष्टम को अपने विचारों एवं नीतियों को राजनीय कार्यों का आधार बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। उसके स्वयंसेवकों को भी शीघ्रपूर्ण विधियों से लोकहित के उत्पादन पर अपने को कृष्टम में परिवर्तित करने का अधिकार बनाने का अधिकार रहता है। वह निश्चय ही लोकहित को बढ़ावा देता है। उत फालीसादी अथवा साम्यवादी अधिनायकतंत्र से उत्पन्न होता है, जिले के कृष्टम के साथ मदमाप को विद्रोह समझा जाता है। उतके उतका परिणाम मतभेद रहने वाले समाज का उपमान, मुख्यतः या दोष तक ही लक्ष्य है।

इस प्रकार राजनैतिक लोकहित की साधना के बिना लोकहितकारी राज्य केवल उत प्रकार का ही लक्ष्य है, जिले के प्रकार बिना आत्मा के शरीर होता है।

सामाजिक लक्ष्य

लोककल्याणकारी राज्य का उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक लक्ष्य भी व्यवस्था करना भी है। लोककल्याणकारी राज्य को चाहिए कि वह जाति, वर्ग, अथवा रंग आदि को हट करे तथा सब प्रकार के व्यक्तिगत मताओं को हट करे कि समाज में समानता उत्पन्न करे। प्रत्येक व्यक्ति का जो समाज में जन्म होता है, जीवन लक्ष्यी लक्ष्य को परिपूर्ण अन्य के लक्षण के लिए नहीं किया जा सकता और ना ही किसी व्यक्ति को अन्य से कम महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। लोकहितकारी राज्य अपने कानूनों तथा संस्थाओं द्वारा व्यक्ति के लिए कानून लक्ष्यी समानता तथा अपनी उन्नति के अवसर लक्ष्यी समानता को व्यवस्था

क्रेट । यही सामाजिक समता के लिए उपेक्षित है ।

प्रक्रियाओं का लोकन्यायकारी धारणा का उदय कुछ मुख्य
- रकों ने राज्य के कार्यक्षेत्र को काफी संकुचित कर दिया
व्यक्तिवादियों ने राज्य को एक आवश्यक सुरक्षित माना व
मनुष्य के अधिकारों को प्रधानता दी । इनके अनुवाद प्रत्ये
व्यक्ति यह निर्णय स्व स्वतः अपने में लक्ष्य है कि उसे
सिद्धि या अर्थ है । इन विचारधारा का परिणाम यह हुआ कि
प्रतियोगिता का युग शुरू हुआ जहाँ वही व्यक्ति एक लक्ष्य
या जी कि अधिक दृष्टि या अर्थ दृष्टि ले गी लक्ष्य था
(Survival of the fittest) । इस विचारधारा के प्रतियोगिता (व्यक्त
लोकन्यायकारी राज्य को कल्पना राजकीय शक्तियों ने की
को अन्त दिया — पूँजीपति वर्गों और मजदूर वर्गों । पूँजीपतियों
द्वारा श्रमिकों का शोषण किया गया इसके भी इन पूँजीपतियों
के हाथों में लिफ्ट राई तथा उल पूँजी के वास्तविक
उत्पादकों के लिए जीवन निवाह करना शक्ति हो गया ।
पूँजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने
यह विचारधारा जाँच पकड़ने लगी कि सभी प्रकार के उत्पाद
को प्रथम उन अमीर अंगित व्यक्तियों का होना है, ज
वस्तुतः कारखानों तथा खेतों में काम करते हैं । अतः जो उत्पा
होता है, उसका उपयोग उन थोड़े से मालिकों द्वारा न होकर
मजदूरों द्वारा होना चाहिए । इन शोषण प्रधान व्यवस्था के सि
वत्कारी-राजकीय व्यवस्था को उत्पादों उहराया गया है ।
वत्कारी-सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए यह आ
श्रमिक समता गया कि राज्य का वर्तमान पूँजीपती व्यवस्था
बदला जाए और उल लोकन्यायकारी बनाया जाए ।
विचारधारा ने भी लोकन्यायकारी राज्य के उदय में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई । मालिकों के अनुवाद उत्पादकों के वास्तविक श्रम
श्रमिकों को मिलना चाहिए । अतः उत्पादकों को लाभ पूँजीपतियों को न
मिलकर श्रमिकों को मिलना चाहिए । इन विचारधारा का
क्रियात्मक रूप सर्वप्रथम इस में देखा जा सकता है, जहाँ 1917
की महान् क्रान्ति ने जाँच के उत्पादकों शोषण को अन्त
कर दिया ।

आरशाही के स्थान पर श्रमिकों ने एक ही अधिनायकत्व का उदय हुआ- जिलों विदेशी लोगों का निर्देयतापूर्ण दमन करते हुए लड़के लिए आर्थिक सुख और कर्मिण्डन उगीया पर आधात समाज की स्थापना की

- कल्याणकारी लोकतन्त्र तथा मताधिकार के विस्तार में भी शताब्दी के अंत तक जहां भी लोकतन्त्र था, वहां मताधिकार बड़ा सीमित था। अतः जनता के बहुत बड़े भाग की आपाज-शासन में नहीं था और राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों के हितों की उपेक्षा की जा सकती थी। सन् 1832 ई. प्रिंस ने सुधार अधिनियम द्वारा मताधिकार बड़ा और उनके बाद 20वीं शताब्दी के भारत आदि अधिकांश राज्यों में भी मताधिकार को स्थापित करना आवश्यक माना गया। जब अधिकांश जनता को शासन में समान प्रतिनिधित्व का अवसर मिला तो उनके हितों की उपेक्षा किया जाना संभव नहीं रहा। किन्तु राज्य के लिए यह आवश्यक हो गया कि पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारों के लिए वह अपने को लोकतन्त्रवादी बनावे- जिलों जनता को राजनीतिक क्षेत्र में उचित सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में भी समानता मिल सके

का विचार द्वितीय विद्रोह के बाद लोकतन्त्रकारी राज्य अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पड़ोसी भी समृद्ध रहे, अन्यथा अपनी समृद्धि को भी खतरा बना रहता है। इसी प्रकार विद्रोह में अंगीकृतता रहते हुए कोई राष्ट्र विरोध यह समझे कि वह प्रगति का लक्ष्य है अथवा राष्ट्रों के हित में बलिदान पर अपना हित लाक्षणिक कर लेता है, तो यह स उल्लाप है। राष्ट्रिय लोकतन्त्र की भावना को स्थायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि किसी राष्ट्रविरोध के हित लाक्षणिक के साथ उभरे-

- राष्ट्रिय हित लाक्षणिक का ही स्थान रखा जाए और विभिन्न राष्ट्रों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के स्थान पर पारस्परिक सहयोग एवं सह-अस्तित्व को बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता लोकतन्त्रकारी- के अर्थ कला तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अर्थ में अर्थ उगी- यथा ही को देना लोकतन्त्रकारी राज्य के लिए आवश्यक है। इसी कारण- कलत्र लक्ष्य को आदेश- यथायुक्त परिणत कर के ही लोकतन्त्रकारी- राज्य का आदेश लाकार हा पा 4 24